

अमेरिका के कानून निर्माताओं का चुनाव

लॉरिडा कीज लौंग

अ

मेरिका और संसारभर का ध्यान उत्सुकता से आगे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर केंद्रित है लेकिन ज्यादातर लोग इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि उसी दिन मतदाता नई अमेरिकी कांग्रेस चुनने के लिए भी मतदान करेंगे। दो सदनों वाली यह राष्ट्रीय संसद कई मायनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी ही महत्वपूर्ण है।

मैन के कॉल्बी कॉलेज में शासन के प्रोफेसर एल. सैडी मैसेल बताते हैं कि अमेरिकी संविधान द्वारा स्थापित शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका शाखाएं मिलजुल कर निर्णय तो लेती ही हैं, एक-दूसरे पर नियंत्रण भी रखती हैं।

उदाहरण के लिए :

कांग्रेस के उच्चतर सदन सेनेट को उन संघियों को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी जिन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करना चाहें,

उसे राष्ट्रपति द्वारा राजदूत, संघीय न्यायाधीश, मंत्रिमंडल के सदस्य के पद पर की गई नियुक्तियों को भी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी,

100 सदस्यीय सेनेट के दो-तिहाई बहुमत की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी नहीं कर सकते;

राष्ट्रपति कानून भी प्रस्तावित नहीं कर सकते, वह केवल कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित और पारित कानूनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं,

राष्ट्रपति हालांकि कानूनों को वीटो कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के शामिल हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की 236 सीटें यानी 54.2 प्रतिशत

सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने का तीसरा उपाय न्यायिक शाखा है। संविधान तैयार करते हुए अमेरिकी गणतंत्र के संस्थापकों ने सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित रखने पर विशेष रूप से ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने तभी स्वेच्छाचारी ब्रिटिश राजा और संसद से स्वतंत्रता पाई थी।

संसदीय प्रणाली में जहां मुख्य

कार्यकारी का चुनाव संसद के बहुमत से होता है, वहीं अमेरिकी मतदाता राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति की जोड़ी, सेनेट सदस्य, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। इन सभी के लिए मतदान एक ही मतपत्र पर किया जाता है।

मैसेल बताते हैं, “फिर से चुने जाने के लिए कांग्रेस के सदस्य दल के नेताओं पर निर्भर नहीं होते और अक्सर अपने मतदाताओं के हितों को देखते हुए मतदान करते हैं, भले ही मुद्दा उनके दल की नीतियों से मेल न खाता हो।” लेकिन सच यह भी है कि अगर वे दल की नीतियों के ज्यादा ही विरोध पर उतार दिखें तो कांग्रेस में मतदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक निर्णयक प्रभाव खो बैठेंगे।

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर एम.सलीम किंवर्द्द कहते हैं, “कांग्रेस, जो अमेरिका की संसद है, बहुत गतिशील और प्रतिनिधित्वपूर्ण है और भारत के ज्यादातर विधान दलों से अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका की नीतियां तैयार करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत जैसे देशों के लिए, जिनके अमेरिका से घनिष्ठ और रणनीतिक सम्बन्ध हैं, जो भविष्य में बढ़ेंगे, यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है।”

इस बरस 4 नवम्बर को होने वाले आम चुनाव में कांग्रेस की 470 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें 435 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की 236 सीटें यानी 54.2 प्रतिशत

संविधान का गठन करने वालों की इच्छा थी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य अपने मतदाताओं का असली मायनों में प्रतिनिधित्व करें। इस सदन के सदस्यों की संख्या अधिक रखी गई ताकि सदस्य अपेक्षाकृत छोटे लेकिन समान जनसंख्या वाले मतदान क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें। उदाहरण के लिए कम जनसंख्या वाले राज्य अलास्का का सदन में एक ही प्रतिनिधि है जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैलिफोर्निया के 53 प्रतिनिधि हैं।

लेकिन सेनेट में नहीं से रोड आइलैंड की भी दो सीटें हैं और विशाल कैलिफोर्निया की भी दो ही सीटें हैं। गणतंत्र के संस्थापक चाहते थे कि बड़े राज्य छोटे राज्यों के हितों के विपरीत मतदान न कर पाएं, इसलिए सभी को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा सेनेटों का कार्यकाल लम्बा रखा गया ताकि वे तत्कालीन सरोकारों के दबाव में आए बिना, मुद्दों पर अधिक निरपेक्ष भाव से विचार करके ही मतदान करें।

बहुमत है, 199 सीटें रिपब्लिकन पार्टी के पास हैं। अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों में पदस्थ सदस्यों का प्रदर्शन अक्सर अच्छा रहता है। इसलिए निर्वत्मान सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण खाली हुई सीटों या मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त हुई सीटों के चुनावों की दौड़ देखने लायक होगी।

सेनेट का चुनाव आखिरी घड़ी तक सरगर्मी और रोमांच से भरा सिद्ध हो सकता है। सेनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीयों के 49-49 सदस्य हैं, दो स्वतंत्र सदस्य भी हैं जो डेमोक्रेटों के साथ मतदान करते हैं। उच्च सदन का नियंत्रण किसी भी पार्टी के हाथ में जा सकता है। वैसे रिपब्लिकन पार्टी को अधिक नुकसान हो सकता है क्योंकि उस की 21 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कुल 12 सीटों पर ही मतदान होगा।

संविधान का गठन करने वालों की इच्छा थी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य अपने मतदाताओं का असली मायनों में प्रतिनिधित्व करें। इस सदन के सदस्यों की संख्या अधिक रखी गई ताकि सदस्य अपेक्षाकृत छोटे लेकिन समान जनसंख्या वाले मतदान क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें। उदाहरण के लिए कम जनसंख्या वाले राज्य अलास्का का सदन में एक ही प्रतिनिधि है जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैलिफोर्निया के 53 प्रतिनिधि हैं।

लेकिन सेनेट में नहीं से रोड आइलैंड की भी दो सीटें हैं और विशाल कैलिफोर्निया की भी दो ही सीटें हैं। गणतंत्र के संस्थापक चाहते थे कि बड़े राज्य छोटे राज्यों के हितों के विपरीत मतदान न कर पाएं, इसलिए सभी को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा सेनेटों का कार्यकाल लम्बा रखा गया ताकि वे तत्कालीन सरोकारों के दबाव में आए बिना, मुद्दों पर अधिक निरपेक्ष भाव से विचार करके ही मतदान करें।

अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं।

सेनेट उच्च सदन है

- 100 सदस्य, हर राज्य से दो सदस्य
 - छह वर्ष का कार्यकाल
 - हर दो वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का चुनाव
- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निचला सदन है
- 435 सदस्य, सभी के निर्वत्मान क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर
 - दो वर्ष का कार्यकाल
 - सभी का चुनाव हर दो वर्ष बाद

मैसेल कहते हैं, “अक्सर ऐसा होता है कि एक दल क्लाइंट हाउस को नियंत्रित करता है दूसरा दल कांग्रेस के एक या दोनों सदनों को।” इसका अर्थ यह हुआ कि अक्सर नए कानून बनाते हुए या बड़े फैसले लेते हुए राष्ट्रपति और कांग्रेस के अगुआ एक-दूसरे से सहमत होते हैं। इसका परिणाम है अमेरिकी नीतियों में दीर्घकालीन स्थायित्व।

किंवर्द्द कहते हैं, “कांग्रेस में दोनों दलों के समर्थन के बिना कोई राष्ट्रपति सफल नहीं हो सकता। मैकेन राष्ट्रपति बनें या ओबामा, उन्हें दोनों सदनों का सहयोग चाहिए होगा।”

विधायिका की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कांग्रेस कांग्रेशनल समितियों को जिम्मेदारियां सौंपती हैं जो किसी खास मुद्दे के विशेषज्ञों का समूह होती हैं।

एसी ही एक समिति है यू.एस.सेनेट कमिटी ऑन फ़ारैन रिलेशन्स। फिलहाल इसके अध्यक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ आर. बिडेन, जू. हैं। सबसे पुरानी कांग्रेशनल समितियों में से एक यह समिति अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विदेश विभाग, यू.एस. एजेंसी फ़ारैन इंटरनेशनल डबलपर्सेंट, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन और पीस कोर के काम की अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैलिफोर्निया के 53 प्रतिनिधि हैं।

सी. मल्फर्ड के नामांकन पर स्वीकृति की मुहर इसी समिति ने लगाई थी। 30 मई को विस्कांसिन के वरिष्ठ डेमोक्रेट सेनेटर रस फ़ीनगोल्ड यू.एस.सेनेट कमिटी ऑन फ़ारैन रिलेशन्स के प्रतिनिधि के तौर पर भारत आए। इस वर्ष की शुरुआत में इस समिति के अन्य सदस्य सेनेटर बिडेन, सेनेटर जॉन केरी और सेनेटर चक हैगेल भी भारत आए थे। यू.एस. सेनेट कमिटी ऑन फ़ारैन रिलेशन्स के कार्यक्षेत्र में आंतकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अर्थिक प्रगति, और परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल हैं।

सरकार की कार्यकारी शाखा के सदस्य जैसे विदेशमंत्री कोंडोलीज़ा राइस को कांग्रेस के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और उसके समक्ष अपने कार्य के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं। संविधान की शर्त के अनुरूप राष्ट्रपति तक को अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन अभिभाषण के माध्यम से विधान दल के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

इस लेख को तैयार करने में अमेरिकी विदेश विभाग के व्यारो ऑफ इंटरनेशनल इन्फ़ोर्मेशन प्रोग्राम्स, ऐरेन श्वार्ट्ज और लीसा स्वेनार्स्की डि हरेरा से सहयोग प्राप्त हुआ।